Statement—I

Number of cases and amount of central excise duty involved in the evasion of duty of textiles during last three years.

(Rs. in lakhs)

Year	No. of cases	Amount involved
1992-93	446	2123.75
1993-94	469	1339.08

1994-95 —Details are being collected and will be laid on the Table of the House.

Statement—II

Statement showing the Revised Estimate and actual collections in respect of fabrics of man-made filament yarn and fabrics of man- nade staple fibre during 1992-93, 1993-94- and 1994-95.

(Rs. in crores)

	1992-93		1993-94		1994-95
	RE	Actual	RE	Actual	R.B.E.
(i) Fabrics of man-made filament yarn	400 00	377.60	450.00	478.33	502.20
(ii) Fabrics of man-made staple fibre	330.00	346.44	390.00	436.33	577 70

No separate targets/actual collections are maintained for powerloom/ mill sector.

Duty concession to 'manufacturers

5968. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no provision in the Central Excise rules and regulations to ensure that the concessions granted by Government in the excise duty to the manufacturers is necessarily passed on to the consumers;

(b) if so, the reasons for such a shortcoming in the rules and regulations and what are the steps taken to ensure that every paise of the excise concession granted by Government is passed on to the common-man; and

(c) if not, the reasons for granting excise duty concession to the manufacturers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI (M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) The Central Excise Duty concessions are granted to serve different objectives, which inter-alia, may include export promotion, protection to small scale industries, improving competitiveness of the domestic manufacturing sector through reduction in input costs. Their impact on price is also sometimes one of the intended objectives. The market prices, however, are determined by a variety of factors, such as demand

and supply, cost of inputs, local taxes, marketing costs, etc. which are variable. It is, therefore, not feasible, nor does Central Excise law have a provision, to ensure that duty concessions are reflected in the market prices.

However, the concerned administrative Ministries in the Government hold periodical discussions with the trade and industry and also monitor prices. It is seen that the duty concessions granted recently have often resulted in bringing down the manufacturers' prices.

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्ति

5969. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 और 1993–94 के वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितने लोगों का बीमा किया गया तथा उनसे कितनी धनराशि प्रीमिब यम के रूप में प्राप्ति की गई ;

(ख) बीमा कराने बाले व्यक्तियों को बीमा पालिसी जारी करने के लिए निगम द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ग) बीभा पालिसियों में से कितनी पालिसियां प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण समाप्त हो गई ; और

(घ) इस तरह समाप्त हुई बीमा पालिसियों के कारण निगम को कितनी राशि का नुकसान वहन करना पड़ा और उसका क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 1992–93 और 1993–94 के दौरान बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के बारे में उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और इस सूचना को एकत्रित करने में आ वाली लागत और प्रयास इसकी उपयोगिता के अनुरूप नहीं होंग । फिर भी, जारी की गई पालिसियों की संख्या और जीवन बीमा निगम द्वारा अंकित प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय नीचे दी गई है :–

वर्ष	जारी की गई नई पालिसियों की संख्या	प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय (करोड़ रुपये में)
1992–93	99,57,348	1609.16
1993–94	1,07,25,633	1890.63

(ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उपरोक्त नई पालिसियों के संबंध में किया गया व्यय 1992–93 में 1046.49 करोड़ और 1993–94 में 1210 करोड़ रु० था ।

(ग) वष 1992–93 और 1993–94 के दौरान जारी की गई नयी पालिसियों में से व्यपगत पालिसियों की संख्या 31.3.94 तक, 1992–93 में 20,03,976 और 1993–94 में 1,39,780 थी ।

(घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जीवन बीमा में लाभ और हानि की सामान्य कारोबार संबंधी संकल्पना का कोई स्थान नहीं है । तथापि, पालिसी धारकों को भुगतान के लिए उपलब्ध कुल अधिशेष पर (जो प्रत्येक वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन से प्राप्त होता है) व्यपगमन के कारण दबाव पड़ता हैं परन्तु उसकी मात्रा निश्चित करना कठिन है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता

5970. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण विकास